ALL INDIA BANK OFFICERS' CONFEDERATION

(Registered under the Trade Unions Act 1926, Registration No.:3427/Delhi)
State Bank of India Officers' Association
04th Floor, SBI Administrative Unit, No. 86, Rajaji Salai, Chennai- 600 001
Phone: 044-25227170 Tel/Fax 044 25227170
E-Mail: aiboc.sectt@gmail.com

Date: 20.05.2017

प्रेस विज्ञप्ति

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ, जो लगभग 2,85,000 सदस्य संख्या के साथ भारत में अधिकारी वर्ग का वृहत्तम ट्रेड यूनियन है, सूचना प्रोद्धयोगी उद्योग में की जा रही छटनी का पुरजोर निंदा करता है । सूचना प्रोद्धयोगी क्षेत्र के समस्त बड़ी कम्पनियों जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, काग्निजेंट आदि ने जो अपने कर्मियों की छटनी प्रारम्भ की है, से पूरे देश में रोजगार विहिनता एवं जीवन यापन का डर पैदा हो गया हा ।

यद्यपि सूचना प्रोद्धयोगी कम्पनियों ने कहा है की कर्मचारियों के छटनी, कर्मियों के वार्षिक मूल्याकन एवं अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों की सामंजस्यता बनाए रखने हेतु किया गया है परंतु अमेरिका एवं अन्य विकसित देशों के सुरक्षात्मक नीतियों के कारण उन देशों के कम्पनियों पर दबाव बढ़ा है कि आउट सोर्सिंग में मात्र अपने देश के कम्पनियों को ही महत्व दें । इस कारण से भारत की सूचना प्रोद्धयोगी कम्पनियों के विकास पर दुष्प्रभाव पड़ा है । अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के योजना "Buy American Hire American" तथा H-1B वीसा की परिवर्तित नीति के कारण स्थिति बिगड़ी है । अमेरिका को H-1B वीसा में लगभग 86% के लाभार्थी भारतीय हुआ करते थे परंतु ये संख्या60% या कम पर आ गई है इन कम्पनियों के पास अब अमेरिका में अमेरिकिनों को अपने यहाँ नौकरी देने के अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं है ।

छटनी किए गए कर्मचारियों ने न केवल अपने जीवन यापन का माध्यम खोया है वरन कम कार्यक्षमता के व्यक्ति के रूप में पहचान से भविष्य में रोजगार के उनके अवसरों पर प्रश्न चिन्ह लगा है । भविष्य में कानून संबंधी किसी भी पचड़े से बचने के लिये इन सूचना प्रोद्धयोगी कम्पनियों ने अपने कर्मचारियों को निम्न मानदंडो के अनुसार आँका है । साधारणत: सूचना प्रोद्धयोयोगी कम्पनियों में लागू प्रगति मूल्यांकन के तरीकों से सभी कर्मी का मूल्यांकन अनुचित रूप से निम्न स्तर पर होता है तथा इस मूल्यांकन का उसके द्वारा संदर्भित राजस्व संकलन से प्रायः कोई सम्बन्ध नही होता । उचित व्यापारिक परिवेश में इस सूचना प्रोद्धयोगी कम्पनियों ने अत्यधिक धन अर्जित किया है अत: उन्हे लाभ का कुछ हिस्सा अपने कर्मचारियों की गुणवत्ता को ठीक करने में खर्च कर अपने कर्मचारियों के निकासी रोकनी चाहिए ।

ज्ञातब्य है कि वर्ष 2014 के वृहद चुनाव प्रचार के दौरान हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से रोजगार के अवसर बढ़ाने के वायदे पर ही सरकार बनाई थी । जबकि सच्चाई ये है अब सरकार गठन के तीन साल बाद रोजगार के क्षेत्र में कोई विकास नही है तथा इतनी बड़ी संख्या में छटनी पर सरकार मौन दर्शक है । ये देश के जनता के साथ धोखा नही तो और क्या है ? एक तरफ सरकार विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते कर रही है तथा विदेशी कम्पनियों को हमारे देश में व्यापार प्रारम्भ करने का निमंत्रण देने में व्यस्त है जबकि सरकार से अपेक्षा थी कि वह विभिन्न देशों को हमारे देश से Labour तथा Professionals के स्वतंत्र आवागमन की मांग करें एवं उसको निश्चित करावे ।

पुन: स्पष्ट है कि जब अधिक संख्या में लोग बेरोजगार होंगे तो वे बाकी अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेंगे जो कि विकरालता ले सकती है चूंकि कम्पनियों को व्यापार घटा है, परिणाम स्वरूप कम्पनियों में छटनी की है, क्योकि व्ययों के बढ़ते रहने से नुकसान में बढ़ोत्तरी होनी ही थी । सरकारी आंकड़ो के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है परंतु रोजगार में वृद्धि में भारत पीछे गया है । अंतराष्ट्रीय औसत के विरूद्ध भारत ने प्रति इकाई वृद्धि के विरूद्ध 2/3 रोजगार ही पैदा किए हैं ।

आर्थिक विकास की दिशा रोजगार परक होनी चाहिए मात्र सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि विकास को मापने का एकमात्र तरीका नही है । हम सरकार एंव नीति निर्माताओं की विचारधारा में परिवर्तन चाहते हैं । सरकार को युवाओं के भविष्य से खेलने की अनुमति नही दी जा सकती है । हमारे सरकार से कड़े शब्दो में मांग है कि हमारी भारत सरकार वृहद स्तर पर सूचना प्रोद्धयोगी कम्पनियों में की जा रही छटनी में हस्तक्षेप करें एवं तेजी से बढ़ती बेरोजगारी पर रोक लगाए । अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ सूचना प्रोद्धयोगी क्षेत्र के कर्मचारियों के संघर्ष में उनके साथी है और उनसे अपेक्षा करती है कि प्रत्येक कंपनी में ट्रेड यूनियन का गठन का प्रयास करें ।

(डी0 टी0 फ्रैंको)
महासचिव
9445000806
ngcfranco@gmail.com